(b) A target of planting 65 lakhs of trees by the Railways at selected stations and 55 lakhs of trees by the State Forest Departments along the railway track in between stations (total 120 lakhs) has been fixed for 1985.

(c) Railway land along the track has in the past been licensed for cultivation purposes. It has been decided that such land should be taken back for tree plantation under Prime Minister's 20-Point Programme. Accordingly, Railways have been advised not to renew such licences where it is proposed to hand over land to the Forest Departments for tree plantation.

Sinking of dredger at Paradip Port

2022. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that two dredgers namely 'Konark' and 'M.O.L. 3' sank at the Paradip Port, if so, what is the valuation of these dredgers;

(b) whether it is a fact that the channel will be closed for entry of the ships if the sinking dredgers are not cleared; if so, what steps are being taken in this regard;

(c) whether responsibility has been fixed on the persons for the loss and sinkage; and

(d) if not, whether Government propose to order an enquiry in the matter, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes Sir. The Dredger 'Konark' was purchased in 1968 at a cost of Rs. 1.50 crores. The Dredger MOT III was procured by Government of India at a cost of Rs. 5 crores in 1971 and was tranferred to DCI in 1976 for Rs. 333.80 lakhs.

(b) There is no danger at present of the channel being closed for entry of ships.

(c and (d) A preliminary enquiry has been ordered by the Director General (Shipping) under the Merchant Shipping Act, 1958. The report is awaited.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गड़बड़ी

2023. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे छुट्टी यात्रा रियायत (लीव ट्रेवल कन्सेशन) के मामले में अनियमितताएं तथा भारी गड़बड़ी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री०के० सी० पन्त) : (क) और (ख) वर्ष 1983–84 के दौरान और 1984–85 की पहली तिमाही के दौरान विश्वविद्यालय ने अवकाश यात्रा रियायत के सम्बन्ध में किए गए दावों में तेजी से हुई वृद्धि को नोट किया। अतः विश्वविद्यालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान 1 जुलाई, 1982 से किए गए दावों की चयनात्मक आधार पर जांच करने का निर्णय किया। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी उनके द्वारा दावा की गई गलत राशि को लौटाने के लिए निर्देश दिया और जून, 1984 तक गैर-भुगतान दावे को वापस लेने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप 53 लाख रुपए के बिल लौटाये गए हैं। विश्वविद्यालय ने 30 जून, 1984 तक प्रस्तुत शेष दावों को जांच करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या न्यायिक जांच के लिए प्रथमत कोई मामला बनता हैं, एक समिति क गठन किया है।